

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक (पीठासीन अधिकारी: रतन लाल योगी, आर.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र सं० - 190/2017

प्रविष्टि दिनांक - 5.9.2017

निर्णय दिनांक - 27.1.2020

उपखण्ड

1. कमलेश पुत्री उर्मिला, जाति जाट निवासी ग्राम अरनियानील, तहसील व जिला टोंक
2. सीमा पुत्री उर्मिला, जाति जाट निवासी ग्राम अरनियानील, तहसील व जिला टोंक
3. सन्तोष पुत्री उर्मिला, जाति जाट निवासी ग्राम अरनियानील, तहसील व जिला टोंक
4. सावित्री पुत्री उर्मिला, जाति जाट निवासी ग्राम अरनियानील, तहसील व जिला टोंक
5. सोना पुत्री उर्मिला नाबालिग उम्र 17 साल जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता कैलाश पुत्र राधाकिशन जाति जाट निवासी अरनियानील तहसील व जिला टोंक

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकरण पुत्र केसरा जाति जाट निवासी ग्राम निमोला तहसील व जिला टोंक
2. सीता पुत्री केसरा जाति जाट निवासी ग्राम निमोला तहसील व जिला टोंक
3. सम्पत पुत्री केसरा जाति जाट निवासी ग्राम निमोला तहसील व जिला टोंक
4. आशा पुत्री रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम निमोला तहसील व जिला टोंक
5. तहसीलदार टोंक
6. उप पंजीयक टोंक

प्रतिपक्षीगण

उपस्थित- श्री पी०के० जैन-अभिभाषक प्रार्थीगण

श्री शिवजीलाल चौधरी-अभिभाषक प्रतिपक्षीगण

निर्णय

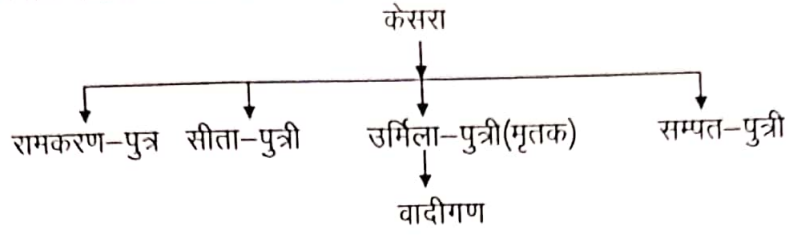
दावा बाबत-घोषणा खातेदारी, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपने वाद पत्र बाबत घोषणा खातेदारी, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा के साथ प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण सं० 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी की भूमि ख.न. 184, 228, 246, 285, 297, 332, 944, 950, 951, 1014 किता-10 कुल रकबा 42 बीघा 5 बिस्वा सम्पूर्ण ग्राम निमोला तहसील टोंक तथा ग्राम निमोला तहसील टोंक के ख. न. 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 368, 369, 375, 376, 377, 379, 380, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 401, 406, 409, 410, 506, 507, 508, 370, कुल किता-34 कुल रकबा 98 बीघा 14 बिस्वा मे हिस्सा 1/11 प्रार्थीगण का है शेष हिस्सा अन्य लोगो का है जिसका कोई विवाद नही है। उक्त आराजी पूर्व में प्रतिपक्षीगण 1 ता 3 एवं प्रार्थीगण की माता स्वर्गीय उर्मिला पुत्री केसरा के नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। उर्मिला का देहान्त हो चुका है जिसके स्थान पर उसके हिस्से की खातेदारी की भूमि को प्रार्थीगण जो उसके वारिसान पुत्रिया हैं, के नाम अंकित करनी चाहिए थी। परन्तु बिना किसी अधिकार के नामान्तरकरण सं० 864 दिनांक 20.9.2006 ग्राम पंचायत लाम्बा से मिली भगत करके प्रतिपक्षीगण 1 ता 3 ने चुपचाप अपने नाम नामान्तरकरण तस्दीक करा लिया जबकि प्रतिपक्षीगण सं० 1 ता 3 को उर्मिला के वारिसान का अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थीगण उर्मिला के स्थान पर उसके नाम दर्ज भूमि के वास्तविक खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। उक्त भरा गया नामान्तरकरण अवैध है। ग्राम पंचायत ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

प्रार्थीगण के हितो के विरुद्ध नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। प्रतिपक्षी सं० 1 ता 3 व उर्मिला स्वर्गीय केसरा के वारिसान का है। केसरा का सजरा निम्न प्रकार है:-



उक्त शजरे के अनुसार केसरा के एक पुत्र व तीन पुत्रिया थी जिनका सभी का हिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में अंकन था। उर्मिला का देहान्त के बाद उसका हिस्सा उसके वारिसान में निहित है परन्तु नाजायज रूप से प्रतिपक्षीगण 1 ता 3 ने अपने नाम करा लिया। जबकि उर्मिला के स्थान पर प्रार्थीगण काबिज है। प्रार्थीगण उर्मिला के स्थान पर खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी है। प्रतिपक्षी सं० 1 ने जमाबंदी में अंकन का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिपक्षी सं० 2 व 3 का हिस्सा जरिये त्याग पत्र अपने नाम करा लिया। जबकि उन्हें किसी प्रकार त्याग पत्र करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार त्यागपत्र का तस्दीक नामान्तरकरण सं० 891 भी गैर कानूनी है। प्रतिपक्षी सं० 1 ने अवैध तरीके से भूमि अपने नाम दर्ज करवाकर ख.न. 228, 246, 285, 297, 337 किता-5 रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा नुमाईशी दानपत्र बिना किसी अधिकार के व बिना कब्जे के चुपचाप अपनी पुत्री प्रतिपक्षी सं० 4 के पक्ष में करवाया है और उसका नामान्तरकरण 926 तस्दीक किया गया है जो प्रारम्भतः शून्य है। ऐसे अंतरण से प्रतिपक्षी सं० 4 को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। प्रतिपक्षी सं० 1 व प्रतिपक्षी सं० 2 अपने नाम दर्ज भूमि को रहन दान बेचान, प्रार्थीगण को बेदखल करने व अनावश्यक विवाद करने पर आमादा है। इस कारण उनको जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वाद निर्णय तक पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः प्रतिपक्षी सं० 1 ता 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पाबन्द किया जावे कि वह स्वयं या अन्य किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेकाशत की भूमि को उनके हिस्से व कब्जेकाशत में हस्तक्षेप नहीं करे। भूमि का रहन, दान, बेचान आदि नहीं करे

इसके पश्चात प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिपक्षी सं० 1 ता 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रार्थनापत्र स्वीकार नहीं है। प्रार्थनापत्र अंकित शजरा स्वीकार है शेष इबारत स्वीकार नहीं है। प्रतिपक्षीगण रिकार्डेड खातेदार है और रिकार्डेड खातेदार को कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिपक्षी सं० 1 व प्रतिपक्षी सं० 4 का ही वास्तविक रूप से कब्जाकाशत है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि से कोई वास्ता नहीं है। प्रार्थीगण उर्मिला पुत्री केसरा जो ब्याहता पुत्री थी और जिसका विवाह काफी वर्षों पूर्व अरनियानील में हुआ था और वही निवास कर रही थी। उर्मिला का देहान्त 2006 में हो चुका है। प्रार्थीगण 1 ता 3 एवं स्व० उर्मिला के पिता केसरा पुत्र श्रवण का देहान्त वर्ष 1992 में हो चुका है। ऐसी स्थिति में उसके पश्चात भरा गया विरासत का नामान्तरकरण में पुत्र रामकरण प्रतिपक्षी सं० 1 के अलावा उर्मिला, सीता व सम्पत के नाम गलत रूप से अंकित कर दिये गये जबकि सन 2005 से पूर्व पिता की मृत्यु होने पर कानूनन पुत्रियों को अचल सम्पत्ति में किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है। कानूनन जो अधिकार प्रदान किये गये हैं वह अधिकार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में सन 2006 से लागू है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि में प्रार्थीगण का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। उर्मिला का अपने पिता की भूमि बाबत भरा गया नामान्तरकरण सं० 864 ग्राम पंचायत द्वारा सही रूप से स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार सीता व सम्पत पुत्रिया केसरा का नाम भी गलत अंकित हो जाने के कारण उनके द्वारा प्रतिपक्षी सं० 1 के हक में हकत्याग कर दिया गया। दान पत्र दिनांक 4.6.2007 ख.न. 285 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा ग्राम निमोला में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि बहक अम्बे पार्वती जी अर्धागिनी श्री महादेव शंकर भगवान बिराजमान कोठयारी जाट मोहल्ला निमोला एवं आशा पुत्री रामकरण जाति जाट के हक में ख.न. 228, 246, 285, 297, 332 दान पत्र करवाया गया है और दानग्रहिता अपने अपने हिस्से पर काबिज है। प्रार्थीगण को उक्त भूमि के किसी भी भाग पर कब्जा नहीं है। प्रार्थीगण उसके वारिसान है जो भी शादी शुदा है अपने अपने

रामकरण अतिकारी
श्री 08 (राम)

ससुराल में रहती है। ग्राम निमोला की आराजी से उनका कोई वास्ता नहीं है और ना ही कब्जा है। प्रार्थनापत्र में चाहा गया अनुतोष गलत है प्रार्थनापत्र खारिज योग्य है।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप में नामान्तरकरण सं० 864, 891, 926, जमावंदी संवत 2063-2066, संवत 2051-54, 2047-2050, 2071-2074, खसरा गिरदावरी संवत 2074, आदि प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में अधिवक्ता द्वारा निम्न नजीरे प्रस्तुत की गई।

RBJ (23)2016 page no 142144,468-474

RBJ (20)2013 page no 275-280, 216-222

RBJ (22)2015 page no 299-302, 544-549

RRD -14-5-2018 page no 328-331

RRT-2016(1) page no 29-42

हमने प्रार्थनापत्र पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। बहस का पृथक से विवेचन नहीं किया जा रहा है। प्रार्थीगण के नाम खातेदारी की घोषणा एवं हक अधिकार संबंधी तथ्य, साक्ष्य दस्तावेजों से वाद निर्णय के समय तय किये जायेंगे। प्रार्थीगण, उर्मिला पुत्री केसरा के वारिसान है यह तथ्य नामान्तरकरण सं० 864 व केसरा के पारिवारिक शजरे से साबित है। साथ ही प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी शजरे को स्वीकार किया गया है और उर्मिला को केसरा का वारिस तथा प्रार्थीगण को उर्मिला का वारिस स्वीकार किया गया है। हमने उर्मिला की मृत्यु उपरान्त भरा गया नामान्तरकरण का अवलोकन किया गया जिसमें पटवारी द्वारा उर्मिला के स्थान पर कॉलम सं० 9 में उर्मिला के वारीसान के नाम अंकित किये गये हैं जिसे भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी स्वीकार किया गया है। लेकिन पंचायत व कोरम द्वारा यह स्वीकार नहीं किया गया। ग्राम पंचायत को गलत अंकन को अस्वीकार करने का अधिकार है ना कि किसी व्यक्ति के वैध वारिसान के नामों के अंकन को रोकना। यहां पर ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण पूर्णतः अवैध है। चूंकि प्रार्थीगण उर्मिला के विधिक वारिसान है और हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विधिक वारिसान में पुत्री व पुत्रियों का समान हक व अधिकार है। इस प्रकार प्रार्थीगण का उर्मिला के विधिक वारिसान होने के नाते उक्त विवादित भूमि में हक व हिस्सा निहित है जिसे ग्राम पंचायत या अन्य किसी को भी वंचित करने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त अधिनियम की अवहेलना करते हुए नामान्तरकरण तस्दीक किया गया जो अवैधानिक है। अतः प्रार्थनापत्र पृथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

चूंकि प्रार्थीगण उर्मिला के वारिसान है और उर्मिला उक्त भूमि की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थी उसकी मृत्यु उपरान्त उसकी विरासत के नामान्तरकरण में उसके विधिक वारिसान का नाम अंकित नहीं करना अवैध तथा कानून की अवहेलना करना है, जिसे न्यायालय में चुनौति दी जा सकती है। यदि उक्त नामान्तरकरण की समय रहते अपील की जाती तो उक्त नामान्तरकरण शून्य घोषित किया जाता। ग्राम पंचायत को मृतक के वारिसान के नाम हटाये जाने का कोई अधिकार नहीं है। उसके द्वारा किया गया उक्त कृत्य शून्य व अपने अधिकारों के दुरुपयोगी की श्रेणी में आता है। लेकिन दूसरी ओर प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र नामान्तरकरण सं० 891 को भी गलत बताया है। चूंकि सीता व सम्पत उक्त भूमि में रिकार्डेड सहखातेदार है, और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार कोई भी सहखातेदार अपना हिस्सा अन्य सहखातेदार के हक में जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र से हक त्याग कर सकता है। अतः उक्त हकत्याग का नामान्तरकरण अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। लेकिन नामान्तरकरण सं० 864 द्वारा प्रार्थीगण को उनके हक व हिस्से से अनाधिकृत व अनुचित रूप से वंचित किया गया है। उक्त अंकन राजस्व रिकार्ड में त्रुटिपूर्ण है और इसके पश्चात भरे गये अन्य नामान्तरकरण सं० 925 व 926 भी त्रुटिपूर्ण व अवैध है तथा प्रार्थीगण के हितों के विपरीत है उक्त नामान्तरकरणों से प्रार्थीगण का हिस्सा प्रभावित होता है। प्रतिपक्षीगण द्वारा अपने जवाब में यह भी अंकित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिपक्षी सं० 1 व प्रतिपक्षी सं० 4 का ही वास्तविक रूप से कब्जाकाश्त है, प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है, लेकिन काश्तकारी अधिनियम के अलोक में भूमि पर कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। एक रिकार्डेड सहखातेदार के वारिस होने के कारण उनके हिस्से

उपखण्ड अधिकारी
टीक (राज.)

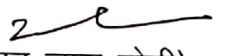
अनुसार भूमि पर काश्त करने का प्रार्थीगण को पूर्ण अधिकार है। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।

चूंकि प्रार्थीगण महिलाएं हैं और प्रतिपक्षीगण द्वारा किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण की भूमि में मजाहमत किये जाने, भूमि को वाद निर्णय तक बेचान करने व रहन, दान करने से हानि प्रार्थीगण को होने की संभावना है। इससे पूर्व भी प्रतिपक्षी सं० 1 ने राजस्व रिकार्ड में तन्हा अंकन फायदा उठाते हुए भूमि को रहन व दान कर दिया है। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में जाता है। इस प्रकार प्रार्थनापत्र के तीनों घटक प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने के कारण, प्रार्थीगण, प्रतिपक्षीगण को वाद निर्णय तक पाबन्द कराने की अधिकारी है। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरे प्रकरण पर चस्पा होती है। अतः यह न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

फलतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भूमि ख.न. 184, 228, 246, 285, 297, 332, 944, 950, 951, 1014 किता-10 कुल रकबा 42 बीघा 5 बिस्वा सम्पूर्ण तथा ख.न. 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 368, 369, 375, 376, 377, 379, 380, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 401, 406, 409, 410, 506, 507, 508, 370, कुल किता-34 कुल रकबा 98 बीघा 14 बिस्वा में हिस्सा 1/11 ग्राम निमोला तहसील टोंक स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षी 1 ता 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा, वाद निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि वे किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण के हिस्से की कब्जेकाश्त में मजाहमत व मदाहखलत नहीं करें, भूमि का रहन, दान, बेचान नहीं करें। राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसलशुमार होकर, नंबर से कम की जाकर, मूल वाद में शामिल की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.1.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रतन लाल योगी)
आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी, टोंक